

है तनखाह के साथ। केवल एक जगह जहाँ हमने कुछ ज्यादा सहूलियत दी है। वह हमारे बार पसंनलस है और उनके लिए एवियेशन रिस्क या बार रिस्क की वजह से हमने कोई प्रीमियम नहीं बढ़ाया है, बाकी हमारे यहाँ छोटा काम होने से और दूसरे कामों के साथ यह काम होने से इसमें खर्च कम होता है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि एल०आई०सी० में खर्च ज्यादा क्यों होता है, उसके लिए मैंने जरूर कहा था कि उसको दूसरे विभाग को देखना है और वह उसको देखे कि वहाँ खर्च ज्यादा क्यों होता है। लेकिन साथ ही आप यह भी याद रखें कि जो उनके काम करने वाले हैं उनकी भलाई की बात भी हमको देखनी होती है। हम दूसरों की तरह काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो राजनारायण जी ने कही, उसके लिए जो उनके मन में कुछ न कुछ होता ही है जिसको उन्हें कहना चाहिए। जब वह खड़े होते हैं तो इन्दिरा जी के लिए बिना कुछ मनगढ़ंत कहे वह रह नहीं सकते। वैसे हर व्यक्ति को अधिकार है कि भले ही वह किसी का रिश्तेदार हो, नहीं तरीके से अपना काम कर सकता है और इस संविधान के रहते हुए हम किसी पर कोई रोक नहीं लगा सकते और मैं समझता हूँ कि राजनारायण जी भी सोचेंगे कि इसमें किसी पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। जो पोलिटिक्स में आए उस पर आप आक्रमण कीजिए लेकिन भलमनसाहत का तकाजा यह है कि हम दूसरों पर छोटें न उछालें।

श्री राजनारायण : श्रीमन् मेरी व्यक्तिगत सफाई यह है कि मेरी कोई आदत नहीं है किसी पर आज़ेप करने की। साफ बात यह है कि सोनिया गांधी को ओरियंटल फायर इंश्योरेंस से 10 हजार रुपया मिलता है। (Interruptions) मैं किसी पर आरोप नहीं करता हूँ लेकिन (Interruption) वह 10 हजार पाती है।

श्री गुणानन्द ठाकुर : श्रीमन् इस तरह से गलत बातें बताने का मौका इनको नहीं देना चाहिए। इस तरह ने लोकतन्त्र नहीं रहेगा।

(Interruption)..

SHRI P. L. KUREEL URF TAUB : Sir, he is in the habit of making..

MR CHAIRMAN : Please resume your seats. Next question.

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : नहीं पाती है।

Payment of Electricity Arrears

*615. SHRI QASIM ALI ABID:

SHRI MAQSOOD ALI KHAN: SHRI GANESH JAL MALI: SHRI IBRAHIM KALANIYA: SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Starred Question 233 given in the Rajya Sabha on 2nd May, 1974 and state :

(a) whether the dispute regarding Payment of electricity arrears between the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Municipal Corporation has since been settled; and

(b) If so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (a) and (b) No, Sir. The Lt. Governor, Delhi made an effort to resolve the issues but as no agreement was forthcoming he suggested that the matter might be referred for arbitration as earlier agreed to by the two local bodies. Government have accepted the suggestion and necessary steps are being taken in this regard.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: Sir, Delhi is a city of growth and challenges. It has been suffering from inadequacies and inefficiency of basic civic services. This is obviously attributable to the inefficiency of the Municipal Corporation of Delhi. Therefore, I would like to know, in the first instance, what is the actual amount claimed and what is the actual amount admitted by the New Delhi Municipal Committee.

SHRI OM MEHTA : It is about Rs. 4 crores that is being demanded by D.M. C. But the N.D.M.C. has not admitted anything : they are challenging the amount.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN : May I also know from the hon'ble Minister what is [the present position of the proposal for setting up an autonomous electricity board for Delhi, and if the proposal is under consideration of the Government how soon this is going to be set up as electricity should be taken away from the Municipal Corporation of Delhi as soon as possible ?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Khursheed Alam Khan.

SHRI OM MEHTA : My Ministry does not deal with it, It is the Minister of Irrigation and Power who is to look into it. So I would not be able to enlighten my friend on this issue.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN : But this matter was under consideration of the Home Ministry in the past.

MR. CHAIRMAN : Now he says it is not under his Ministry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : May I know from the Home Minister whether it is not a fact that the Central Government has instructed the D.D.A. in this matter of electricity arrears not to pay to the Municipal Corporation of Delhi the amount due by way of salary of the sweepers ? That is the background. The Central Government obviously wants to embarrass the Municipal Corporation. They have advised the D. D. A. not to pay to the Municipal Corporation the amount that is to be paid to the Class IV workers of the Municipal Corporation.

MR. CHAIRMAN : That is your information.

SHRI OM MEHTA : The question is regarding D.M.C. and N.D.M.C.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : They are connected. /

SHRI OM MEHTA : D.D.A. has nothing to do with it. Arrears are to be paid by the N.D.M.C. and it is for the Corporation to pay to its employees. If they have to get it from the D.D.A. they can settle with it. But we have not directed anybody not to pay them.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह बात सही है कि डी० एम० सी० के ड्यूज इतने अधिक हैं कि उनके न देने के कारण दिल्ली के अन्दर बिजली की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को दिक्कत आती है, यदि हां तो इसके लिए आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे ? एन०डी०एम०सी० जो केवल आपकी बाड़ी है, गवर्नमेंट की बाड़ी है, उसमें निर्वाचित लोग नहीं हैं, उसको गवर्नमेंट को अफसर देखते हैं, आपके अपाइन्टड लोग उसको देखते हैं और यह लोग उनको पैसा नहीं देते हैं तो इस बात को देखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है इस लिए मैं चाहूंगा कि क्या आप एक्शोरस देगे कि जितनी जल्दी हो सकेगा जितना कारपोरेशन का पैसा है वह सारा दिलवा दिया जाएगा ?

श्री ओम मेहता : यह मामला इतना आसान नहीं है . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कारपोरेशन को काम नहीं करने नहीं देगे यह इनकी साजिश है ।

श्री ओम मेहता : यह मामला डी० एम० सी० और एन० डी० एम० सी० में 1959 से चल रहा है। 1959 में ऐसा था कि जो सप्लाय हुई इलेक्ट्रिसिटी की एन० डी० एम० सी० को तो उस समय कहा गया कि टैक्स लिया जाए और वह टैक्स डी० एम० सी० को दिया जाए इसके बाद दोनों लोकल बाडीज ने जितने ल्युमिनरीज है उनकी राय जाननी चाहिए । उसमें सीतलवाड़, सी० के० दफतरी एटारनी जनरल और श्री एस० बी० गुप्त सोलिसिटर जनरल थे इनकी राय थी और उसके बाद जब दोनों की राय कन्ट्राडिक्ट रही तो यह मामला लैफ्टीनैन्ट गवर्नर के पास गया । लैफ्टीनैन्ट गवर्नर इस बारे में अपनी राय दी लेकिन वह राय एन० डी० एम० सी० को मंजूरी नहीं थी ।

1970-71 में आखिर यह फसला हुआ कि आबिड्युशन कराया जाए । क्योंकि यह मामला बहुत पुराना है जब तक इसका आबिड्युशन नहीं होगा इसका हल नहीं निकल सकेगा । इसी कारण यह मामला अटका हुआ है अभी हमारे पास यही चीज है कि इसका आबिड्युशन कराया जाए और हम इसके लिए तैयार हैं । मैं फिर कारपोरेशन से भी कहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी आबिड्युशन कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जिसका हपया है उसको मिल सके । हम तो किसी को नहीं बचाना चाहते हैं हम तो यह चाहते हैं यहां की जितनी सिविक सर्विसेज है, एफिशिएन्ट रन करती रहे और अगर डी० एम० सी० को कुछ रूपया एन० डी० एम० सी० पर ड्यू है तो वह उसको जरूर मिले । मैं समझता हूं जब तक आबिड्युशन नहीं होगा यह मामला हल नहीं हो सकता और रूपया भी नहीं मिल सकता । इसको हल करने के लिए जरूरी है कि कारपोरेशन आबिड्युशन के लिए तैयार हो ।

पिछले दिनों डी० एम० सी० और एन० डी० एम० सी० दोनों ने माना था कि आबिड्युशन होगा लेकिन बदकिस्मती से दास माहब जो थे, जो जज थे उन्होंने नहीं माना । मैं फिर अपील करता हूं कि दोनों लोकल बाडीज आबिड्युशन के लिए मान जाएं और फैमले के बाद जिसका रूपया हो उसको मिल जाए ।

श्री राजनारायण : आबिट्रेंटर किमको बनाया जाएगा ?

माननीय सदस्य : आपको ।

श्री राजनारायण : अगर आबिट्रेंटर मुझ को बनाया जाएगा तो मैं इसका फैसला तीन दिन में कर दूंगा ।

*553. [The Questioner (Shri Lakshmana Mahapatra was absent. For answer vide Col 30 infra.]